हरियाणा राज्य

बनाम

प्रेम चंद और अन्य

14 दिसंबर 1989

[न्यायमूर्ति बी सी रे और न्यायमूर्ति एस रत्नवेल पांडियान]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 137 और 145-निर्णय की समीक्षा-बनाए गए नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग।

उच्चतम न्यायालय नियम, 1966: आदेश XL, नियम 1-आपराधिक कार्यवाही में निर्णय की समीक्षा- केवल अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटि के आधार पर ।

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 376-पीड़ित का चरित्र या प्रतिष्ठा-सजा देने में प्रासंगिक नहीं- परंतुक के अंतर्गत शमन करने वाली या कम करने वाली परिस्थिति नहीं है धारा 376(2)।

इस न्यायालय ने इस मामले में 31.1.1989 को आईपीसी की धारा 376 (2) के प्रावधान को लागू करते हुए दोनों प्रतिवादियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए और कारावास की सजा को 10 साल से घटाकर 5 साल करने का फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता राज्य ने उक्त फैसले की समीक्षा की मांग की है।

पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते हुए, यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1. उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XL नियम 1 के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटियों तक सीमित है। तत्काल मामले में, अभिलेख में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है जिससे निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता हो। [498 एफ]

पी एन ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, **[1980] 4 एससीसी 680**; *सो चंद्र कांता और अन्य बनाम शेख हबीब*, **[1975] 3 एससीआर 933**; *श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य*, **[1983] 4 एससीसी 104**, पर भरोसा किया गया।

2. बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए, पीड़ित की एकमात्र गवाही को स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि ही एक स्पष्ट संकेत है कि इस अदालत का विचार था की आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आरोपी के अपराध का निर्णय लेने या सजा देने के मामले में पीड़ित के चरित्र या प्रतिष्ठा का कोई संबंध या प्रासंगिकता नहीं है। ऐसे कारक धारा 376 के दायरे और उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अलग हैं और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) के परंतुक की सहायता से उप-न्यूनतम सजा को लागू करने के लिए कभी भी कम करने या बढ़ाने वाली परिस्थितियों के रूप में काम नहीं कर सकते हैं।

3. इस न्यायालय ने न तो पीड़िता को संदिग्ध चरित्र और स्वच्छंद आचरण वाली महिला के रूप में चित्रित किया और न ही फैसले के किसी भी हिस्से में उसके चरित्र या प्रतिष्ठा का कोई संदर्भ दिया, बल्कि यह दिखाने के सीमित उद्देश्य के लिए शाब्दिक अर्थ में "आचरण" अभिव्यक्ति का उपयोग किया कि पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा 28.3.1984 को उसकी जांच किए जाने तक उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में लगभग 5 दिनों तक किसी को न बताने का उसने कैसे व्यवहार या आचरण किया था। "आचरण" शब्द का उपयोग पीड़ित के चरित्र या प्रतिष्ठा के संदर्भ में नहीं किया गया था। [500 बी-सी]

4. यह न्यायालय नारीत्व की शालीनता और गरिमा को बनाए रखने में किसी से पीछे नहीं है और इस न्यायालय ने निर्णय में ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं किया है कि

बलात्कार पीड़िता का चरित्र, प्रतिष्ठा या स्थिति किसी को सजा सुनाते समय न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। बलात्कारी [500 डी] 497

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: समीक्षा याचिका (आपराधिक) सं 241-242/1989

में

1986 की आपराधिक अपील संख्या 544-545

याचिकाकर्ता के लिए महाबीर सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए ए. एन. मुल्ला, एस. बी. उपाध्याय।

न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश

न्यायमूर्ति रे: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1986 की आपराधिक अपील संख्या 544-45 में इस पीठ द्वारा 31 जनवरी 1989 को दिए गए फैसले की समीक्षा के बाद एक विवाद पैदा हो गया था, जिसके तहत इस न्यायालय ने दोनों प्रतिवादियों/अभियुक्तों की सजा की पुष्टि करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के प्रावधानों को लागू करके प्रत्येक प्रतिवादी के संबंध में कारावास की सजा को 10 साल से घटाकर 5 साल कर दी थी। हरियाणा राज्य ने फैसले की समीक्षा करने और "मामले की परिस्थितियों में आवश्यक अन्य या आगे के आदेश पारित करने की मांग करते हुए उपरोक्त याचिका दायर की है।"

शुरुआत में, हम इस न्यायालय द्वारा पहले ही सुनाए गए आपराधिक मामले में निर्णय की समीक्षा के दायरे की जांच कर सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति देता है, लेकिन ऐसी विशेष शक्ति का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए इस न्यायालय के नियमों के अनुसार और उनके अधीन किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश XL, नियम 1 में प्रावधान है:

"न्यायालय अपने फैसले या आदेश की समीक्षा कर सकता है लेकिन सिविल कार्यवाही में संहिता के आदेश XL VII, नियम 1 में उल्लिखित आधार और आपराधिक कार्यवाही में अभिलेख में त्रुटि के आधार को छोड़कर समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

इस न्यायालय ने इसके निर्णयों की एक श्रृंखला में आपराधिक मामलों में फैसला सुनाए जाने या आदेश दिए जाने के बाद समीक्षा के दायरे की जांच की है। हालाँकि हम उन सभी निर्णयों का हवाला नहीं दे रहे हैं, हम कुछ का उल्लेख कर सकते हैं।

पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम पंजीयक, सर्वोच्च न्यायालय भारत, [1980] 4 एस. सी. सी. 680 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने नियम पर विचार करते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः

> "नियम (आदेश XL, नियम 1), पहली नजर में सिविल कार्यवाही में आदेशों की समीक्षा के लिए आधारों के समूह को व्यापकता प्रदान करता है, लेकिन आपराधिक कार्यवाही में आधार को सीमित करता है केवल 'अभिलेख में स्पष्ट त्रुटियाँ के आधार पर'।"

सो चंद्र कांता और अन्य बनाम शेख हबीब, [1975] 3 एससीआर 933; और *श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य और अन्य*, **[1983]** 4 एससीसी 104 को भी देखें।

हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, जब वर्तमान मामले की जांच ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में की जाती है, हम अभिलेख में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जिससे निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता होती और इस तरह ये समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाने योग्य हैं।

हमने विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री राजिंदर सच्चर की दलीलें सुनी हैं, जिन्होंने हालांकि शुरू में अपनी दलीलें पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से शुरू कीं अंततः इन समीक्षा याचिकाओं में राज्य की ओर से अपनी दलीलें आगे बढ़ाईं विद्वान वकील श्री महाबीर सिंह द्वारा राज्य की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन पर। श्री आर. के. पी. शंकर दास जिन्होंने अपने तर्कों को महिला संयुक्त मोर्चा की ओर से आगे बढ़ाया कहा कि उनके तर्कों को श्री राजिंदर सच्चर के तर्कों के पूरक के रूप में माना जाए। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुल्ला, उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए

हालाँकि हमने पाया है कि समीक्षा याचिकाएं इस आधार पर खारिज की जा सकती हैं कि अभिलेख में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं है, तथापि, हमारे सामने उपस्थित विभिन्न विद्वान वकीलों द्वारा की गई विस्तृत दलीलों को देखते हुए, हम निम्नलिखित टिप्पणियाँ करना पसंद करेंगे।

मामले के तथ्य आपराधिक अपील में संक्षेप में बताए गए हैं और, इसलिए, इसे फिर से दोहराना आवश्यक नहीं है। कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी/अभियुक्त कि अपीलों पर सुनवाई के दौरान, यह विद्वान बचाव पक्ष के वकील द्वारा आग्रह किया गया है कि पीड़िता सुमन रानी संदिग्ध चरित्र और स्वच्छंद आचरण के साथ भद्दे और कामुक व्यवहार की महिला थी और इस प्रकार उसके संस्करण स्वीकार करने योग्य नहीं है। मामले के गुण-दोष के आधार पर काफी बहस के बाद, तर्क केवल सजा की मात्रा के संबंध में सीमित था। पूरे मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पीड़ित के आचरण को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 376(2) का प्रावधान लागू किया जा सकता है और दंडात्मक प्रावधान के तहत प्रदान की गई अनिवार्य सजा अनावश्यक है।

इस बिंदु पर, हम यह बताना चाहेंगे कि बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए पीड़िता सुमन रानी की एकमात्र गवाही को स्वीकार करना ही अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है कि इस अदालत का विचार था कि पीड़िता के चरित्र या प्रतिष्ठा का आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी के अपराध का फैसला करने या सजा देने के मामले में कोई लेना-देना या प्रासंगिकता नहीं है। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि ऐसे कारक धारा 376 के दायरे और उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अलग हैं और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) के प्रावधान की सहायता से उप-न्यूनतम सजा देने के लिए दंडात्मक रुख को कम करने या बढ़ाने के रूप में कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में, हमने फैसले में ही अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकृति के अपराध को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और उचित दंड से निपटा जाना चाहिए।"

हमने पीड़िता सुमन रानी को संदिग्ध चरित्र और स्वच्छंद आचरण वाली महिला के रूप में वर्णित नहीं किया है न ही हमारे फैसले के किसी भी हिस्से में उसके चरित्र या प्रतिष्ठा का कोई संदर्भ दिया गया बल्कि शब्दकोषीय अर्थ में सीमित अभिव्यक्ति "आचरण" का उपयोग यह दिखाने के सीमित उद्देश्य के लिए किया गया कि राम लाल (पीडब्लू-14) द्वारा 22.3.1984 को रविशंकर के विरुद्ध दी गई शिकायत के संबंध में 28.3.1984 को पुलिस उप-निरीक्षक (पीडब्लू-20) द्वारा जांच किए जाने तक सुमन रानी ने अपने ऊपर हुए यौन उत्पीड़न के बारे में लगभग 5 दिनों तक किसी को न बताकर कैसा व्यवहार में कैसे व्यवहार किया था या खुद को संचालित किया था। इस संबंध में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने पीड़ित-सुमन रानी के चरित्र या प्रतिष्ठा के संदर्भ में 'आचरण' शब्द का उपयोग नहीं किया है।

इस मामले से अलग होने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि यह न्यायालय नारीत्व की शालीनता और गरिमा को बनाए रखने में किसी से पीछे नहीं है और हमने

अपने फैसले में ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं किया है कि बलात्कार पीड़िता का चरित्र, प्रतिष्ठा या हैसियत एक बलात्कारी को सजा सुनाते समय न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

G.N.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।